#### टाइम्स ऑफ़ पीडिया

NEW DELHI Page 12 Price ₹ 3.00

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इंसाफ़ की डगर पर

**WEEKLY HINDI ENGLISH URDU** 

WED 15 DEC - TUE 21 DEC, 2021

**VOL. 9. ISSUE 52** 

RNI No. DELMUL/2012/47011

## उपराष्ट्रपति ने २०२५ तक टीबी उन्मूलन का आस्वान किया

उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान में लोगों को प्रमुख भागीदार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, टीबी को पूरी तरह खत्म करने के लिए समाज का जुड़ाव किसी भी अन्य बीमारी के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, कमजोर वर्गों पर तपेदिक का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, टीबी उन्मूलन के लिये बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल और दूसरे क्षेत्रों से भी लोगों को आगे आना चाहिए.

उपराष्ट्रपति ने कहा कि टीबी को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाये और सभी स्तरों पर जन प्रतिनिधियों से जन आंदोलन में लोगों को शामिल करने के लिये आगे आने का आह्वान किया जाये। उन्होंने कहा कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए टीम इंडिया की भावना को अपनाकर बहुआयामी प्रयास की जरूरत है।

श्री नायडु ने जोर देकर कहा कि टीबी के प्रति लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, यह देखते हुए कि



यह बीमारी महिलाओं पर कहीं अधिक असर डालती है। उन्होंने देखा कि महिलाओं को स्वास्थ्य, कल्याण और पोषण में प्राथमिकता न मिलने से वो इस बीमारी का ज्यादा शिकार बनती हैं। उन्होंने कहा, यदि टीबी पाया जाता है तो परित्याग और हिंसा के दुख को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाओं में टीबी के बड़ी संख्या में मामले दर्ज नहीं

किये जाते इसलिये इलाज भी नहीं हो पाता है।

उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से बीमारी के बारे में बेहतर और व्यवस्थित परामर्श, निश्चय पोषण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से बेहतर पोषण सहायता और टीबी से पीड़ित बच्चों, गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं पर विशेष ध्यान देने जैसे उपायों से इसका

मुकाबला करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्यों से डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अपने बल पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से संपर्क करने के लिये तैयार नहीं हैं। 2025 तक पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार के सभी स्तरों से ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए, श्री नायडू ने लोगों की पोषण स्थिति में सुधार, बेहतर संपर्क जांच, बीमारी पर होने वाले खर्च को कम करने, सबसे कमजोर वर्गों को सुरक्षित रखने और पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में टीबी का शीघ्र पता लगाने जैसे कदम उठाने का आह्वान किया। टीबी रोगियों को बड़े पैमाने पर परिवारों, नियोक्ताओं और समाज की अनावश्यक गलत सोच का सामना करना पड़ता है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसे रोका जाना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने महिलाओं पर टीबी के प्रभाव को कम करने के लिए नई रणनीति विकसित करने के तरीके पर इस बैठक में गभीर चर्चा की —पीआईबी

#### Ali Aadil Khan - Editor's Desk

# हिन्दू रवतरे में है? तो कौन सुरिदात है? धुर्वीकरण की धुरी उल्टा घुमा रही सियासत के पाटों को

सिर्फ चुनाव की हद तक, या फिर यह धूर्वीकरण की राजनीती खुद देश के लिए बडा खतरा है. देश में इलेक्टोरल सिस्टम चलते अपराधी और मवाली सियासत में आ गए हैं जो देश को देश की तरह नहीं बल्कि अखाड़े की तरह देखते हैं जहाँ कुश्ती जीतने का हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है. सियासत के मैदान की कुछ मर्यादाएं होती हैं जिनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है.

सियासत अब सेवा का पेशा नहीं बल्कि मेवा खाने का धंदा बन गया है, जाहिर है जब कोई करोडों में टिकट खरीदेगा तो कमाने के लिए उसको भ्रष्टाचार करना ही पड़ेगा, पार्टी फण्ड के नाम पर टिकट बेचने की होड़ ने चुनाव को लोकतंत्र के पर्व की जगह नफरत फैलाने का माध्यम बना दिया है. ईमानदार, मेहनती, शरीफ और सेवाभाव रखने वाला व्यक्ति आज भी सियासत से

आप किस हद तक गलत मानते हैं? क्या शरीफ इंसान उस हमाम में कूदने की हिम्मत नहीं कर पाता जिसमें सब तो नहीं मगर ज्यादातर नंगे हैं.

पार्टी में टिकट देने का पैमाना सेवा, की भी कुछ खराबियां रही हैं, जिसके शिक्षा या सादगी नहीं बल्कि बाहुबली, धनी और पैसा कमाने का धुनि रख दिया गया है. जनता की सेवा करने वाले झंडा, डंडा उठाते रह जाते हैं, दरी और कूर्सियां बिछाते रह जाते हैं जबकि चालबाज नेता विडंबना है हमारे इलेक्टोरल और के हाथ पहुँच जाए. Parliamentary सिस्टम की संसद को साल गुजरने के बाद भी जनता से साथ मांग रहे हैं. अगर सिर्फ अपराधमुक्त संसद का वादा पूरा कर दिया होता तो बहुत से है, तू अगर खुद ही न चाहे तो बहाने हजार हैं. अब दूसरा एक बड़ा मसला कि हिन्दू

ताकतवर सरकार जो हिन्दू वादी होने के देश की भोली जनता के साथ छल कर रहा पहचानना मुश्किल है? या जनता जान बुझकर छली जा रही है. मगर इस पूरे छल

जिहाद की कोख से कई नए कानूनों ने जन्म लिया जो देश के या तो पढे लिखे, बुद्धिजीवी, या फिर क्रांतिकारियों की आपसी भाईचारा, प्यार और सद्भाव की खतरे में है, इससे पहले हिन्दू युवतियां टकराव, द्वेष और जातिवाद, मंदिर मस्जिद,

देश में वोट धुर्वीकरण की राजनीती को दूर रहना चाहता है. यह ईमानदार और खतरे में थीं, देश बाबर कि औलाद के हाथों कब्रस्तान, शमशान, अब्बाजान, चचाजान में चला जाने वाला था, देश की सबसे जैसे फिक्रों से समाज लगातार विभाजन की ओर बढ़ रहा है. इसपर तुरंत रोक न नाम पर ही बनी, फिर कौन है जो ये सब लगी तो देश में अराजकता आम हो जायेगी. टाइम्स ऑफ पीडिया लगातार है, कोई तो है. लेकिन क्या उसको एकता अखंडता पर वीडियोज बना रहा है, लेख और ब्लोग्स भी लिख रहा है. आपसी भाईचारा और साम्पदायिक एकता हमारे के प्रकरण में सिर्फ 12: जनता ही शामिल देश की शक्ति है और विकास का आधार है, है जो देश को ऐसे मकाम पर लेजाकर इसलिए हर हाल में समाज को बंटने से बनकर भ्रष्टाचार में माहिर हो जाता है. यह छोड़ना चाहती है जहाँ से सत्ता विदेशियों रोकने की आवाज हर कोने से उठनी चाहिए. वरना देश हकीकत में शमशान हिंदुत्व खतरे में है, Love जिहाद, और कब्रस्तान में और मलबे के ढेर में अपराधमुक्त करने वाले प्रधान सेवक सात कोरोना जिहाद, चूड़ी जिहाद, UPSC तब्दील हो जायेगा. सड़कों की सफाई अपनी जगह लेकिन दिलों की सफाई होनी चाहिए. चौड़ी सड़कें और ऊची इमारतों की जगह नौजवानो को रोजगार, किसानो को वादे स्वतरू ही पूरे हो जाते. मगर वही बात आवाज को दबाने के काम आया. अब उनकी फसलों के दाम और महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए. तब हर हर महादेव कहीं बात ही नहीं होती. हर तरफ नफरत, और अल्लाह् अकबर के नारों में भी मजा आएगा.

#### समाचार

## किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन १८००१८०५१४५ पर सम्पर्क करे -श्री अमित मोहन प्रसाद

1,52,506 सैम्पल की जांच की गयी, कोरोना के कुल 203 एक्टिव मामले हैं। जिसमें कोरोना संक्रमण के 27 नये मामले आये हैं। प्रदेश में अब तक कुल

स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया तथा अब तक कुल 16,87,604 लोग तक पहली डोज 12,21,53,649 तथा आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल कोविड—19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में दूसरी डोज 6,39,42,939 लगायी गयी हैं।

> श्री प्रसाद ने बताया कि कोविड जा चुकी है। वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 20 3,86,894 डोज दी गयी। प्रदेश में कल है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप तथा अब तक कुल 18,60,96,588 डोज दी

श्री प्रसाद ने बताया कि कोविड 9,09,02,855 सैम्पल की जांच की गयी हैं। रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ

कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे।

—आईटीएन

## शादी मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण जरूरत, रोक क्यूं अमानवीयः मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी का बयान

नई दिल्ली, 20 दिसम्बरए 2021 : ऑल टोक क्यू. इस्लाम या किसी अन्य धर्म में निर्धारित करना कानून के खिलाफ है. यह इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शादी के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है यह महासचिव हजरत मौलाना खालिद विश्वासियों और उनके अभिभावकों के सैफुल्ला रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा विवेक पर है. यदि वह उस पर लगाए गए है कि शादी मानव जीवन की एक दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम है, तो महत्वपूर्ण जरूरत है. जब नशा करने के उसे शादी से मना करना क्रूरता है और लिए कोई निश्चित उम्र नहीं बनाया गया एक वयस्क की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में तो शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए रोक हस्तक्षेप है. शादी के लिए न्यूनतम आय्

किसी के भी हित में नहीं है.

यह कानून दो वयस्कों के नैतिक मूल्यों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि, कम उम्र में शादी करने की प्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है लेकिन कभी–कभी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां लड़की के हित में निर्धारित उम्र से पहले

शादी करना जरूरी हो जाता है। इसलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार से इस तरह के बेकार और हानिकारक कानून बनाने से परहेज करने का आग्रह करता है.

जारीकतार्रू जनरल सेक्रेटरीऑ ऑलइंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

भोजपुरी भाषा को सरकार आठबी अनुसूची में शामिल करे रू जदयू नेता आशीष रंजन



करीब बारह संगठनों ने भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया । जिसमें जदयू के वरिष्ठ नेता आशीष रंजन सिंह ने माँग किया की केंद्र सरकार इस भाषा को अस्टम अनुसूची में शामिल करे श्री आशीष रंजन ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दिया और कहा की मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को विधानसभा में पास कर केंद्र सरकार को

भोजपुरी भाषा मान्यता आदोलन समेत भेजी है और अब यह केंद्र सरकार का दायित्व है कि इस भाषा को अस्टम अनुसूची में शामिल करे। भोजपुरी जन जागरण अभियान पिछले सोलह सालों यह अभियान चला रही है जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए जिसमें संस्था के अध्यक्ष श्री संतोष पटेल जी, जदयू नेता अजय कुमार सिंह, नागेंद्र सिंह,ललन कुमार झा,रणधीर सिंह, बी के पटेल समेत भारी संख्या में लोग शामिल हुए ।

—आईटीएन

## डांस विद इंडिया के फाइनल में पहुंचे मुरादनगर के

सॉल हर्ष बीट द्वारा आयोजित टीवी रियलिटी शो डांस विद इंडिया के टीवी राउंड में देश के कोने कोने से सलेक्टेड डांसर्स ने अपना हुनर दिखाया, जहाँ टीवी राउंड में सबसे ज्यादा, दा बेस्ट इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर व कोरियोग्राफर जावेद अमन सर के स्टूडेंटस थे, फाइनल राउंड में भी सबसे ज्यादा दा बेस्ट के डांसर्स ही पहुचे.

14 डांसर्स ने सेलेक्ट होकर इस रिकॉर्ड को कायम रखा, दा बेस्ट के डायरेक्टर जावेद अमन सर ने बताया कि अगले हफ्ते होने वाले फाइनल में कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहेगा, जिसके लिए



बच्चों को और मुझे दिन रात मेंहनत करनी अरोड़ा, अनवी गर्ग, शनवी त्यागी, कनक होगी. फाइनल में पहुंचने वाले, अनन्या त्यागी, सहसरा राज सिंह, रनवी त्यागी,

आरना त्यागी, शिवांश त्यागी, रोहन बेदी, दिया सैनी, नेहा, अंशिका चौधरी, मलिका त्यागी व हिमाशी मदान है, जिन्होने फाइनल के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी

शो के डायरेक्टर हर्ष कुमार ने बताया कि दा बेस्ट के डांसर्स हमेशा कुछ नया करते है, जिससे शो में चार चाँद लग जाते है. सभी अभिभावकों में खुशी कि लहर है.

नगर वासियो ने जावेद अमन सर व सभी सलेक्टेड बच्चो को बधाई दी व अगले हफ्ते होने वाले फाइनल में सभी के लिए जीत कि प्राथना की.

– सजिद खान

#### NOTICE:

Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

#### Photo Shoot for Global United UN Calendar in Sharda University

Greater Noida. LA Global Foundation and Sharda Launch Pad jointly shot the Global United UN Calendar-2022 in the premise of Sharda University. The School of Media, Film & Entertainment (SMFE) played an important role in this shooting project. This is CSR Global Records Pilot Projects.

Regarding this photo shoot, @Prof. (Dr.) Ritu S. Sood, Dean of SMFE and Dr. Amit Sehgal, Sharda Launch Pad jointly said that this photo shoot is an important step towards making people



aware of the 17 SDG goals of the United Nations. Dr Meenakshi Sawhney Founder president LA Global Foundation, said that our organization is doing a lot of work for women's health, empowerment and child health development. She said that 17 major profiles have been shortlisted for this calendar, whose picture will be published in the calendar of 2022. This calendar will be published digitally and will be sent to all the Ministries and Embassies including 183 countries of the world.

Vote of thanksgiving felicitation ceremony held for all finalist participants Dr Chetna Agrawal, Dr Prachvi Y Raizada, Ms Aarti Trivedi, Mrs Mamta Bankuray in the end.

-Sunit Narula:

## कृतिक खेती पर प्रधानमंत्री का पा

गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अन्य सभी महानुभाव, देश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में जुड़े मेरे किसान भाई-बहन, देश के कृषि सेक्टर, खेती किसानी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देशभर के किसान साथियों से आग्रह किया था, कि नैचुरल फार्मिंग के नेशनल कॉन्क्लेव से जरूर जुड़ें।और जैसा अभी कृषि मंत्री तोमर जी ने बताया करीब करीब 8 करोड़ किसान टेक्नॉलाजी के माध्यम से देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े हुएहैं। मैं सभी किसान भाई—बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य देवद्रत जी का भी हद्य से अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत ध्यान से एक विद्धयार्थी की तरह आज मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं स्वंय तो किसान नहीं हूँ, लेकिन बहुत आसानी से मैं समझ पा रहा था, कि प्राकृतिक कृषि के लिए क्या चाहिए, क्या करना है बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया और मुझे पक्का विश्वास है आज का उनका यह मार्गदर्शन और मैं जानबूझ करके आज पूरा समय उनको सुनने के लिए बैठा था। क्योंकि मुझे मालूम था, कि उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है, प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं है। हमारे देश के किसान भी उनके फायदे की इस बात को कभी भी कम नहीं आंकेगें, कभी भी भूलेंगे

ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव, पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है। एग्रीकल्चर के अलग–अलग आयाम हों, फूड प्रोसेसिंग हो, नैचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हजारों करोड़ रुपए के समझौते उसकी भी चर्चा हुई, उसकी भी प्रगृति हुई हैं। इनमें भी इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है।

आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का और उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सबने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6–7 साल में बीज से लेकर बाजार तक, किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं।

मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का डेढ़ गुणा एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक, अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है।खेती के साथ-साथ पशुपालन, मधुमखी पालन, मत्स्यपालन और सौर ऊर्जा, बायोपयूल्स जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आज द्निया भर में खेती को इन चुनौतियों से दोचार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगाऔर अधिक ध्यान देना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बडी मात्रा में इंपोर्ट करना पडता है।

गुजराती में एक कहावत है, हर घर में बोली जाती है श्श्पानी आवे ते पहेला पाल बांधे। पानी पहला बांध बांधो, यह हमारे यहां हर कोई कहता है... इसका तात्पर्य ये कि इलाज से परहेज बेहतर। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाएं, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती कोकैमिस्ट्री की लैबसे निकालकरनेचर यानि प्रकृति की प्रयोगशालासे जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। ये कैसे होता है, इसके बारे में अभी आचार्य देवव्रत जी ने विस्तार से बताया भी है।हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है। और जैसा उन्होंने कहा उनकी किताब प्राप्त करके भी यूट्यूब पर आचार्य देवद्रत जी के नाम से ढूढ़ेंगें उनके भाषण भी मिल जाएंगे।जो ताकत खाद में, फर्टिलाइजर में है, वोबीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौज़द है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढाती है।

कई एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गोमूत्रहो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं, जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़-सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं-धान-दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सद्पयोग किया जाता है। यानी, कम लागत, ज्यादा मुनाफा।यही तो प्राकृतिक खेती

आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है, उतना ही श्इबा जव इंपबश की ओर बढ रही है। इस ठंबा जव इंपब का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना! इस बात को आप सब किसान साथियों से बेहतर कौन समझता है? हम जितना जड़ों को सींचते हैं, उतना ही पौधे का विकास होता है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। खेती–किसानी के इर्द-गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, परम्पराएँ पोषित हुई हैं, पर्व-त्योहार बने हैं। यहाँ देश के कोने कोने से किसान साथी जुड़े हैं। आप मुझे बताइये, आपके इलाके का खान-पान, रहन-सहन, त्योहार-परम्पराएँ कुछ भी ऐसा है जिस पर हमारी खेती का, फसलों का प्रभाव न हो? जब हमारी सभ्यता किसानी के साथ इतना फली-फूली है, तो

कृषि को लेकर, हमारा ज्ञान-विज्ञान कितना समृद्ध रहा होगा? कितना वैज्ञानिक रहा होगा? इसीलिए भाइयों बहनों, आज जब दुनिया वतहदपब की बात करती है, नैचुरल की बात करती है, आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है, तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पडती हैं।

यहाँ पर कृषि से जुड़े कई विद्वान लोग उपस्थित हैं जिन्होंने इस विषय पर व्यापक शोध किया है। आप लोग जानते ही हैं, हमारे यहाँ ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेकर हमारे पुराणों तक, कृषि–पाराशर और काश्यपीय कृषि सूक्त जैसे प्राचीन ग्रन्थों तक, और दक्षिण में तमिलनाडू के संत तिरुवल्लुवर जी से लेकर उत्तर में कृषक कवि घाघ तक, हमारी कृषि पर कितनी बारीकियों से शोध हुआ है। जैसे एक श्लोक है- गोहितः क्षेत्रगामी च, कालज्ञो बीज-तत्परः. वितन्द्रः सर्व शस्याढ्यः, कृषको न अवसीदति.

अर्थात जो गोधन का, पशुधन का हित जानता हो, मौसम-समय के बारे में जानता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो, और आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। ये एक श्लोक नैचुरल फार्मिंग का सूत्र भी है, और नैचुरल फार्मिंग की ताकत भी बताता है। इसमें जितने भी संसाधनों का जिक्र है, सारे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। इसी तरह, कैसे मिट्टी को उर्वरा बनाएं, कब कौन सी फसल में पानी लगाएँ, कैसे पानी बचाएं, इसके कितने ही सूत्र दिये गए हैं।

कृषि से जुड़े हमारे इस प्राचीन ज्ञान को हमें न सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी जरूरत है। इस दिशा में हमें नए सिरे से शोध करने होंगे, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक फ्रेम में ढालना होगा। इस दिशा में हमारे प्हात जैसे संस्थानों की, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों की बड़ी भूमिका हो सकती है। हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और जीमवतपमे तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस में बदलना होगा। स्इ जव संदक यही हमारी यात्रा होगी। इसकी शुरुआत भी हमारे ये संस्थान कर सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप नैचुरल फार्मिंग कोप्राकृतिक खेती कोज्यादा से ज्यादा किसानों तक ले जाएंगे। आप जब ये करके दिखाएंगे कि ये सफलता के साथ संभव है, तो सामान्य मानवी भी इससे जल्द से जल्द जुडेगें।

नया सीखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी पड़ेगा जो खेती के तौर-तरीकों में आ गई हैं। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है।

पहले केमिकल नहीं होते थे, लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कृषि युग में मानवता सबसे तेजी से फली फूली, आगे बढ़ी। क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी, लगातार लोग सीखते थे। आज औद्योगिक युग में तो हमारे पास टेक्नालजी की ताकत है, कितने साधन हैं, मौसम की भी जानकारी है! अब तो हमकिसान मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर परेशान है उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परपरागत

ज्ञान के द्वारा उपाय दे सकता है। हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं।

नैचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा, वो हैं हमारे देश के 80 प्रतिशत छोटे किसान। वो छोटे किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च, केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी।

प्राकृतिक खेती पर गांधी जी की कही ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है जहां शोषण होगा, वहां पोषण नहीं होगा। गांधी जी कहते थे, कि मिट्टी को अलटना-पटलना भूल जाना, खेत की गुड़ाई भूल जाना, एक तरह से खुद को भूल जाने की तरह है। मुझे संतोष है कि बीते कुछ सालों में देश के अनेक राज्यों में इसे सुधारा आ रहा है। हाल के बरसों में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इनमें से कई तो स्टार्ट-अप्स हैं, नौजवानों के हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना से भी उन्हें लाभ मिला है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस खेती की तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है।

मैं आज देश के हर राज्य से, हर राज्य सरकार से, ये आग्रह करुंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आएं। इस अमृत महोत्सव में हर पंचायत का कम से कम एक गांव जरूर प्राकृतिक खेती से जुडे, ये प्रयास हम सब कर सकते हैं। आप अपनी थोड़ी जमीन पर खुद अनुभव करो। अगर फायदा दिखता है तो फिर थोड़ा विस्तार बढ़ाओं। एक दो साल में आप फिर धीरे– धीरे पूरे खेत में इस तरफ चले जाओगे। दायरा बढ़ाते जाओगे। मेरा सभी निवेश साथियों से भी आग्रह है कि ये समय ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में, इनके उत्पादों की प्रोसेसिंग में जमकर निवेश का है। इसके लिए देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है। हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है।

इस अमृतकाल में दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी और प्रकृति से समन्वय बेहतरीन समाधान हमें भारत से देना है।

आइये, आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएँ। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तब ही बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले, हम मां भारती की मिट्टी का सवधेन, गोबर—धन से करें, तत्वों से करें।

हर देशवासी, हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जनांदोलन बनाएंगे, इसी विश्वास के साथ में गुजरात सरकार का गुजरात के मुख्यमंत्री जी का उनकी पूरी टीम का इसके लिए पूरे गुजरात में इसको जन आंदोलन का रुप देने के लिए और आज पूरे देश के किसानों को जोड़ने के लिए मैं संबंधित सभी का हद्र्य से बहुत— बहुत अभिनंदन करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद !

#### केंद्रीय इस्पात मंत्री का मंडी गोबिंदगढ़ और लुधियाना की विभिन्न इस्पात इकाइयों का दौरा

केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज मंडी गोबिंदगढ और लुधियाना की विभिन्न इस्पात इकाइयों का दौरा किया और क्षेत्र के उद्योग से जुड़े स्थानीय उद्योगपतियों से उनके मुद्दो और समस्याओं पर चर्चा की ।

इस बैठक में ऑल इंडिया स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन (एआईएसआरए), ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन (एआईआईएफए) और मंडी गोबिंदगढ़ फर्नेस एसोसिएशन (एमएफएए) जैसे राष्ट्रीय और स्थानीय संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। संस्थाओं ने माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया और बताया कि 27 साल के बड़े अंतराल के बाद एक केंद्रीय इस्पात मंत्री ने इस क्षेत्र



का दौरा किया है जिससे उन्हें बहुत उत्प्रेरण और संबल मिला है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार सेकेंडरी स्टील सेक्टर पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है और शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें इस सेक्टर से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना के प्रभाव से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

इफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश से देश में स्टील की मांग भी बढ़ रही है। मौजूदा सरकार ने कारोबारियों और व्यवसायियों में विश्वास लाने के लिए कई नियम कानूनों को बदला है जिसका सकारात्मक प्रभाव हुआ है। श्री सिंह ने कहा की मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार 80 करोड़ भारतवासियों को प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त दे रही है जिस पर सरकार ने 260000 करोड रुपए खर्च किए हैं और यह गर्व की बात है कि सारा अनाज भारत के किसानों द्वारा ही उपजाया जा रहा है और आयात नहीं किया जा रहा।। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री के साथ इस्पात मंत्रालय की अपर सचिव, श्रीमती रसिका चौबे भी मौजूद थीं ।

### क्रिश्चियन कॉलेज गोलागंज लखनऊ के प्रांगण में कनटाटा हेबन इन माई हार्ट आयोजित किया गया

दिनाँक 20ध12ध्2021 दिन सोमवार को लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज गोलागंज लखनऊ के प्रांगण में कनटाटा हेवन इन माई हार्ट आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर संजय सोलोमन एवं पूर्व प्राचार्या डॉक्टर प्रोनोती सिंह के द्वारा प्रार्थना एवं बाइबल पाठ से हुआ, तत्पश्चात डॉक्टर ईशा लाल के संचालन में छात्रों के क्वायर समूह के द्वारा विभिन्न गीत गा कर इशू मसीह के



आगमन की खुशियों को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पास्टर हेनरी सैमसन ने प्रभु इशू के अपार एवं अदभूत प्रेम का रमरण किया और उन्हें निराशा में आशा का श्रोत बताया। येशू द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का भी आवाहन किया।

कार्यक्रम के समापन पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बैजू अब्राहम ने कोरोना काल में सफलतापूर्वक कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर ए. रॉबर्टसन, के आशिर्वाचनों के साथ हुआ।

डॉक्टर नोमिता गवन, डॉक्टर ईशा लाल एवं डॉक्टर मनीषा प्रसाद के विशेष सहयोग एवं उपस्थित विभिन्न इकाइयों के शिक्षकों, छात्र एवं छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस कार्यक्रम में डॉक्टर डी जे गोडिन (एम एल ए उत्तर प्रदेश सरकार) एवं विभिन्न शिक्षकों एवं छात्रों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का समापन रेव. संजय वर्मा

#### जीतन राम मांझी अपना मानिसक संतुलन खो बैठे हैं: मनोज कुमार सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री

औरंगाबादरू (बिहार) यह कथन है. रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व 2जनशक्ति पार्टी प्रत्याशी रह चुके मनोज कुमार सिंह का. श्री सिंह ने कहा है कि सुबे के मुख्यमत्री, / नीतीश कुमार के प्रिय माने जाने वाले दलितों के नेता, जीतन राम मांझी द्वारा हिन्दू धर्म एवं ब्राह्णण जाति के विरुद्ध दिया गया बयान यह दर्शाता है कि इनका दिमागी सोच किस हद तक नीचे गिर चुका है जी काफी ही निंदनीय है. इसलिए इस मुद्दे पर लीक जनशक्ति पार्टी,



(रामविलास) औरंगाबाद की टीम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जीतन राम मांझी

द्वारा दिया गया बयान की घोर निंदा करती है इसके अलावे रफीगंज के विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी प्रत्याशी रह चुके एवं प्रदेश सचिव, लोजपा (रामविलास) मनोज कुमार सिंह ने भेट वार्ता के दौरान कहां है कि बिगत संपन्न चुनाव के बाद अभी तक भी बिहार में नीतीश कुमार द्वारा कोई जन कल्याणकारी कार्य नही किया गया है. सिर्फ बिहार की भोली भाली जनता को इन लोगों ने भरमाने का ही काम किया है.

नीति आयोग द्वारा भी इन लोगो को प्रत्येक क्षेत्र में पीछे ही दिखाया गया है. इसका नतीजा है कि ये लोग सिर्फ अपना कुकर्म को छुपाने हेतु ही इस प्रकार के निदनीय बयान देकर जनता को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है. इसलिए हम एवं हमारा टीम इसकी घोर निंदा करते हुए तत्काल इन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर करने का अनुरोध भाजपा नेतृत्व से करते है.

–अजय कुमार पाण्डेय

## शिल्टर होम में बिच्चयों के उत्पीड़न के आरोप में चार महिलाएं गिरफ्त

दिल्लीः दिल्ली सेक्टर-23 थाना इलाके के एक आश्रय गृह (निजी शेल्टर होम) की चार महिला कर्मियों को उत्पीड़न के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. इस आश्रय गृह के कर्मचारियों ने कथित रूप से वहां रह रही लंडकियों का उत्पीड़न किया था.

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने बताया कि बृहस्पतिवार को द्वारका के एक निजी आश्रय गृह की जांच के दौरान दिल्ली महिला आयोग ने पाया कि आश्रय गृह के कर्मचारी लड़कियों को नियम पालन नहीं करने पर बुरी तरह से दंडित करते हैं.

कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया कि महिलाकर्मी सजा के तौर पर उनके प्रावइेट पार्ट्स में मिर्ची का पाउडर डाल देती हैं. पुलिस ने बताया कि इस खुलासे



के बाद चार महिलाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. चारों महिला कर्मियों में से एक कल्याण अधिकारी, एक प्रभारी और दो अन्य कर्मचारी थीं. उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जाच जारी है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोग और पुलिस की जांच में और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं. आरोप है कि जो बच्ची बिस्तर में पेशाब कर देती थी उसे इतनी कडाके की ठंड में ठंडे पानी से नहलाने का दड दिया जाता था.

दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि अगर हमारी कमेटी बच्चियों से बात किए बिना ही आ जाती तो हमें इन घटनाओं की जानकारी ही न मिलती. 6-7 साल की दो बिच्चयों ने आयोग की कमेटी को इन घटनाओं की जानकारी दी थी.

डीसीडब्ल्यू ने बताया कि शेल्टर होम में बच्चियों से साफ—सफाई कराने के लिए एक ड्यूटी चार्ट बनाया गया था जिसे शेल्टर होम में रहने वालीं 6 से 15 साल तक की उम्र वाली लड़कियों के रूम में टांगा गया था. इसी चार्ट के आधार पर उनसे काम कराया जाता था और अगर इस नियम में कोई गड़बड़ी करता था तो फिर उसे कड़ी सजा दी जाती थी.

पुलिस ने बताया कि वे इस मामले में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेल्टर होम में रह रहीं बच्चियों से कोई गलत काम तो नहीं कराया जा रहा था.

## मिश्रा को बर्खास्त न करना सरकार के 'नैतिक दिवालियेपन' का संकेत: प्रियंका गांधी

नई दिल्लीः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने लखीमपुर खीरी मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) के आवेदन की पृष्टभूमि में बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार करना केंद्र सरकार के 'नैतिक दिवालियेपन' का सबसे स्पष्ट संकेत है.

उन्होंने यह भी कहा कि मिश्रा को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मामला दर्ज होना चाहिए.

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, 'अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने से सरकार का इनकार उसके नैतिक दिवालियेपन का सबसे स्पष्ट सकेत है. नरेंद्र मोदी जी, सावधानीपूर्वक धार्मिकता



करने से यह तथ्य नहीं बदल जाएगा कि

का प्रदर्शन करने और धार्मिक वस्त्र धारण जोर देकर कहा, 'अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए और कानून के आप एक अपराधी को बचा रहे हैं.'उन्होंने मुताबिक मामला दर्ज करना चाहिए.'

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अब तक की छानबीन और साक्ष्यों के आधार पर दावा किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के पुत्र और उसके सहयोगियों द्वारा जानबूझकर, सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अजाम दिया गया.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू और कुछ अन्य लोगों पर लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है. इस घटना में और इसके बाद भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.

## धर्म के आधार पर भारत का विभाजन 'ऐतिहासिक गलती' थी: राजनाथ सिंह

नई दिल्लीः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते रविवार को कहा कि 1971 का युद्ध याद दिलाता है कि धर्म के आधार पर हुआ भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी और पाकिस्तान तभी से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में शामिल है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंह ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और भारत-बांग्लादेश मैत्री (पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने) के 50 साल पूरे होने के मौके पर इंडिया गेट पर आयोजित स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर संबोधित करते हुए कहा, 'इस युद्ध ने भारत के सशस्त्र–बलों के बीच एकजुटता के महत्व को दर्शाया है, जिसकी ओर सरकार अब काम कर रही है.

सिंह ने कहा, '1971 का युद्ध हमें बताता है कि धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी. पाकिस्तान का जन्म एक धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन वह एक नहीं रह सका. 1971 की हार के बाद हमारा पड़ोसी देश लगातार भारत में छद्म युद्ध करता रहा.'

उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान आतंकवाद और अन्य भारत विरोधी गतिविधियों के जरिये भारत को तोड़ना चाहता है. भारतीय



सेना ने 1971 में पाकिस्तान की योजनाओं को असफल कर दिया था और अब वह हमारी बहादुर सेनाओं के जरिये आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है. हम सीधे युद्ध में जीते हैं और अब छद्म युद्ध में भी जीत हासिल करेंगे.' सिंह ने कहा, 'आज के बदलते समय में एकजुटता को बढ़ावा देने और हमारी तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण पर चर्चा हो रही है. मुझे लगता है कि 1971 का युद्ध इसका सफल उदाहरण है इस युद्ध ने हमें योजना, प्रशिक्षण और एक साथ होकर लड़ने का महत्व समझाया है.'

उन्होंने 1971 के युद्ध में भारत की जीत की सराहना करते हुए कहा कि इसने

दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल को बदल दिया. सिंह ने कहा, 'भारत हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है.'

उन्होंने कहा कि यह युद्ध न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ था, बल्कि अन्याय और प्रताड़ना के खिलाफ भी था. इसमें पाकिस्तान पर सिर्फ भारत की जीत ही नहीं हुई, बल्कि यह अन्याय पर न्याय, बुराई पर सदाचार की भी जीत थी.

अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा, 'कहीं भी अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है. पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगालियों पर किए गए अन्याय और अत्याचार एक या अन्य प्रारूप में पूरी मानवता के लिए खतरा थे.

पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के लोगों को अन्याय और उत्पीड़न से मुक्त कराना हमारा धर्म, राष्ट्रीय धर्म और सैन्य

रक्षा मंत्री ने कहा, 'यह युद्ध हमारी नैतिकता, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और व्यवहार का उदाहरण है. इतिहास में ऐसा मुश्किल ही देखने को मिलेगा कि युद्ध में किसी देश को हराने के बाद भारत ने इस पर अपना वर्चस्व व्यक्त नहीं किया, बल्कि वहां के राजनीतिक शक्तियों को इसे

उन्होंने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान दिया है.

उन्होंने कहा, 'आज हम बहुत खुश हैं कि बीते 50 सालों में बांग्लादेश ने विकास के मार्ग पर बहुत तेजी से प्रगति की है, जो बाकी दुनिया के लिए प्रेरणा है.'

उन्होंने दोहराया कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही कभी किसी देश की एक इंच जमीन पर कब्जा किया है. उन्होंने कहा, 'आज इस दिन मैं भारतीय सेना के हर जवान के शौर्य और उनके बलिदान को नमन करता हूं, जिसकी वजह से भारत ने 1971 का युद्ध जीता. यह देश उन वीरों के बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा.'

#### गुजरात में धर्मातरण के आरोप में मिशरीज ऑफ चौरिटी के ख़िलाफ मामला दर्ज

वडोदराः गुजरात में मदर टेरेसा द्वारा संस्थापित मिशनरीज ऑफ चौरिटी संगठन के खिलाफ हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने और युवा लड़कियों को ईसाई धर्म की ओर लुभाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के तहत मिशनरीज ऑफ चौरिटी के वडोदरा में संचालित एक शेल्टर होम के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, संगठन ने इन आरोपों से इनकार किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मयंक त्रिवेदी की शिकायत के आधार पर 12 दिसंबर को मकरपुरा पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई.

बालगृह की लड़कियों को ईसाई धर्म के परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने का किया है. शिकायतकर्ता के मुताबिक, ग्रंथों को पढ़ने और ईसाई धर्म की प्रयास करने का अपराध है. जहां संगठन ने ईसाई परंपराओं के अनुसार एक प्रार्थनाओं में भाग लेने को 'मजबूर' किया मिशनरीज ऑफ चौरिटी के प्रबंधन ने जा रहा था.

एफआईआर में कहा गया, 10 फरवरी 2021 से नौ दिसंबर 2021 के बीच संस्थान जान-बूझकर हिंदू भावनाओं को आहत करने की गतिविधियों में शामिल था. बालगृह की लडिकयों के गले में क्रॉस पहनाकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया जा रहा था.

इसके अनुसार, 'लड़कियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्ओर रूम की की मेज पर बाइबल रखा जा रहा था,

ताकि उन्हें बाइबिल पढ़ने को मजबूर परिवर्तन नहीं किया है या किसी को ईसाई एफआईआर में त्रिवेदी ने कहा कि किया जा सके. यह लड़कियों को धर्म धर्म में शादी करने के लिए मजबूर नहीं किसी भी तरह के जबरन धर्मांतरण से इनकार किया है, वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है.

> मिशनरीज ऑफ चौरिटी के एक प्रवक्ता का कहना है, 'हम किसी तरह की धर्म-परिवर्तन गतिविधि में शामिल नहीं हैं. हमारे बालगृह में 24 लड़कियां हैं. ये लड़किया हमारे साथ रहती है और ये हमें जिस तरह से प्रार्थना करते और रहते देखती हैं, ये ठीक उसी तरह से उसका अनुसरण करती हैं. हमने किसी का भी धर्म

हिंदू लड़की को एक ईसाई परिवार में शादी करने को मजबूर किया और शेल्टर होम में रह रहीं लड़कियों को हिंदू होने के बावजूद मांसाहारी भोजन दिया जाता है.

सहायक पुलिस आयुक्त एसबी कुमावत ने कहा कि 'जिला कलेक्टर ने बाल कल्याण समिति की शिकायत के बाद समिति का गटन किया था. कई विभागों के सदस्यों की टीम ने आरोपों की जांच की. पुलिस आरोपों की जांच करेगी और इस संबंध में सबूत इकड्डा करेगी कि क्या ये तर्क सही हैं.

## Imposing Vegetarianism as a Political Agenda

Prof. Ram Puniyani

Recently (December 2021) town planning committee of Ahmadabad Municipal Corporation specifically mentioned that stalls selling nonvegetarian items will not be allowed along public roads and in the 100-meter radius of schools, colleges and religious places. On these lines decisions were also taken by Vadodara, Bhavnagar, Junagadh and Rajkot Municipal bodies. As the hawkers selling these non vegetarian items approached the Court, Court struck down this decision by the authorities.

Surprisingly opposition to non vegetarian food is part of the communal agenda. It is being propagated that non vegetarian food causes violent tendencies. By now it has become a routine for one to hear at different occasions that Muslims are having aggressive tendencies because they consume nonvegetarian food. When probed further the consumption of beef by Muslims is also brought forward. Additionally the point is made that since cow is holy for the Hindus, Muslims at the same time are hurting the sentiments of the Hindus. Lynching on the pretext of cow-beef are a separate chapter by itself.

Two issues have been deliberately intertwined in the social common sense. One is the non vegetarian food causing violent tendencies and the second, the eating of beef by Muslims and thereby hurting the sentiments of Hindus. It is very clear that the definition of non vegetarian food varies from place to place and community to community. Eggs are OK for some vegetarians and strict no for others. Some regard sea food, fish and the like as vegetarian while for others it is non vegetarian food in



all sense of the meaning. Today world over roughly more than 80-90% of the population is non vegetarian so to say. As per a survey conducted by IndiaSpend, around 80 per cent of Indian men and 70 per cent of women consume meat weekly.

While Muslims in India are the object of wrath, the Europeans and Americans etc. do get away easily in this psyche despite having beef-non vegetarian food as the staple diet. In the countries and people who follow the biggest apostle of non violence ever, Lord Gautam Buddha, the consumption of non vegetarian food is no less in quantum. For that matter right here there are innumerable communities for whom beef has been a part of the food habits. Non vegetarianism is prevalent in most communities. Different surveys show that eating non vegetarian food is substantial in most communities including in most states including the one like Gujarat.

There are political over and undertones also in this 'hate nonvegetarians' thinking. One can go to the extent of saying that Vegetarianism is also being used as a social and political weapon to browbeat the minority community. No doubt one has the choice of shifting to vegetarianism with full commitment, but to be intolerant to the non vegetarians and to label the Muslims as having violent personality due to the food habits is a part of political campaign, bereft of any

scientific-psychological rationale today. Historically speaking beefnon vegetarian diet was common food in Vedic times (Cow is essentially food, Atho Annam Via Gau, (cow is verily food)). Swami Vivekanand points out "You will be astonished if I tell you that, according to old ceremonials, he is not a good Hindu who does not eat beef. On certain occasions, he must sacrifice a bull and eat it." (cited in 'The Complete Works of Swami Vivekananda', Vol 3 (Calcutta: Advaita Ashram, 1997, p. 536.)

N. Jha in his book 'Myth of Holy Cow' shows that it was with the rise of agricultural society that the restriction was brought in on cow sacrifice by Lord Buddha. The primary goal was to preserve the cattle wealth. The ardent follower of Buddhism, Emperor Ashok, in one of his edicts to the royal kitchen orders that only as many animals and birds be killed as are necessary for the food in the kitchen. This was to put a brake on the animal sacrifice which was part of the Brahminical rituals. It was as a reaction to this that Brahminism came up to project cow as mother to show that it also has concern for cattle and in due course Brahmanism, and politics around it gave her the status of mother.

As far as the violent personality and food is concerned, not much scientific literature is available to prove the correlation of food with the violent tendencies. Violence is a personality trait, in the realm of

psychology, which is shaped by familial, social and political circumstances, and keeps changing according to the situations.

There are systems of medicine, the traditional one's which classify food according to the Satwik (leading to pure, quiet persona), Tamsik (increasing anger) and Rajsik (royal) but it hasn't been vindicated beyond empirical assertions. Despite some people holding on to human nature correlated to type of food, it is far from being vindicated by any of the modern scientific studies, there is an example of a vegetarian Hitler unleashing the biggest ever genocide. There are groups of people taking to vegetarianism and latest vogue is that of veganism. The element of religiosity is not mixed up here. Neither should people be intolerant to the ones who consume non vegetarian food. The phenomenon being observed amongst the sections influenced by communalism operates at the level of religiosity. Vegetarianism here is a part of one's political agenda so to say. As it is being mixed up with religion; it becomes associated with emotions and that's where the strong rejection of non vegetarians in the neighborhood comes in. Many housing societies refuse those who eat non vegetarian food.

In Ahmadabad I observed that landlord/ladies will barge into the kitchen of their tenants to ensure the strict vegetarianism is adhered to. Now amazingly this has been turned as one more tool of demonize Muslims. Overall as seen in parts of Gujarat vegetarianism is propagated and imposed in such an aggressive way, these orders of Municipalities reflect that. One can certainly say that those propagating vegetarianism in such a fashion is intolerant to the hilt.

### **AMUOBA Lucknow deliberate forthcoming UP Elections.**

A state level meeting was organized by Aligarh Muslim University Old Boys Association Lucknow and a resolution was unanimously passed to build up pressure on the government to safeguard the interest of the minorities. This meeting was to discuss and deliberate the the forthcoming UP elections. Prof. Shakeel Ahmed President AMUOBA, Kidwai, LUCKNOW initiating the discussion emphasized that till today minorities are being targeted as only vote bank. He added that this must end now and the government should give due importance to minorities, who form 20% of the state population.

The caste and religion politics must end and the exploitation of the minorities must stop, he further added. Muslims who have contributed immensely towards the freedom movement of the country are the most backward, socially, economically, and educationally. It was unanimous that pressure groups must be created all over



India, to compel the government, to address the minorities problems now. It was also decided to meet all the prominent political parties namely, CONGRESS, SP, BSP, AIMIM, BJP, and discuss the same.

The demand to confer Bharat Ratna on Sir Syed Ahmed was also passed as a resolution. It was felt that when Madan Mohan Malviya, Founder of BHU, had been conferred with the Bharat Ratna award, then why not Sir Syed Ahmed, be awarded the same?

AMUOBA being an intellectual body of the muslims, and spread all over the world demands, said that all political parties, must include in their manifesto the following main points like representations of muslims in government body proportionate to their vote percentreservations for muslims, age, nearly 8% in higher educational the establishment of institutions, good schools..IJT, ITI'S and vocational centers in minority and dalit dominated areas. Tarique Siddiqui former President of AMUOBA, lucknow said that if secular parties are not going to fight for muslims, then AMU will be forced to come on streets, just like the kisans. They were supported in their andolan by all secular parties. He further added that if we muslims build university and the government doesn't give it recognition, then it will b just a building structure. Wat will v do with it?? Hence we need recognition by government.

They also demanded that a minority university, in the memory of Sir Syed Ahmed be set up in Lucknow, to resolve the minority character of AMU, which is still in court. Abolition of the religious cap of article 341, scrapping of the UP Government order to promote urdu language, for urdu medium schools and for officials use in government too. And lastly to expedite the court proceedings, for early justice to muslims wrongfully convicted and languishing in jails for a longer period.

His Eminence Prof Dr MADHU KRISHAN, The Chairman Cum Chief Rector / Chancellor of The American University USA & United Nations University USA (AUGP / UNUGP USA) & Chairman Of UN GDO & Diplomatic Mission USA, Initiated Mega Peace Movement In African Countries to unite all African Countries /Nations To Make African Continent self sustainable developed & Strong Continent.

3 days teaching & training seminar was Successfully done in Dodoma, The Capital City Of Tanzania followed by Convocation on 5 th December at the Conference hall of the Regional Commissioner Of Dodoma, Govt of Tanzania, where many African Countries representatives participated, which includes India, South Asian countries. Top Leaders. Ministers. Member of Parliament, Inter faith leaders etc participated in well attended event.

His Eminence Prof Dr Madhu Krishan in his key note address dwelt at length on the topic & in his motivational speech he expressed the Need of bringing Unity Among Diversity & to join this Nobel Peace Mission which he started 4 decades back with the Goal to build up a transformed Civilization of Peace Loving - Peace Living - Peace Practicing global community of global citizens to transform global citizens to become PEACE Builder &



Ultimately Nation Builder. All participants from various Countries have taken the Oath also( which was lead by H.E. Prof. Dr. Madhu Krishan ) to become the Peace Builder & Ultimately Nation Builders & to proclaim the GOPEL of Peace through out the World. H.E Prof. Dr. Madhu Krishan as an Eminent Scientist expressed that there are very high potentials of natural resources, natural Minerals, Rivers etc in whole of Africa, hence all these gift of God for African Continent it is Possible to become the Strongest Continent in this earth Planet which can support all other continent of this Earth Planet.

He has all scientific technology to extract & make use of all Natural resources for Eco- Friendly USA for the Humanity, H.E Prof. Dr. Madhu Krishan further added in his Key Note Speech of more than 2 Hours in the Government Conference hall of the Regional Commission of Dodoma. Some Names of Precipitants, Achievers who were honoured by H.E. Prof. Dr. Madhu Krishan with Doctorate Degree (Honoris Causa) from USA Based The American University USA -AUGP USA (www.augpusa. education - Incorporated Legally, with USA Federal Govt Registration No. 7670276 8100, SR # 20197712450 ; Secretary of The First State Accreditation / Authentication No.203858464. Affiliated to The United Nations University for Global Peace Usa with Federal Govt of USA (www.unugp.education -Registration Number 6816639 8100 SR# 20184990447, Secretary of State Authentication No. 202828725 & The Apex Body of Indian Confederation of Universities) are as follows: Dr Burton Saulo Yuda, Hon. Dr Joseph Kasheku Msukuma, Hon. Dr Japhet Ngailonga Hasunga, Dr. Florah Godwin Lauo, Bishop Dr Jason John Mutashongera, Dr. Fredrick Andrea Solo, Bishop Dr Eugene Kalisa Mulisa, Dr Simon Baha Panga, Dr Geofrey Jackson

Masawe, Dr. Joshua Charles Ndisa, Bishop Dr. Robert Nathanael, Dr. Elpendo Ntaika Mreah, Dr. Elina Nziku Kayanda, Dr Daudi Felix Ntibenda, Bishop Dr. Eliah Edward Mauza. Event was organized by Bishop Dr. Eliah Edward Mauza, Director & Ambassador Of AUGP USA (Tanzania Chapter) & his team Bishop Dr Burton Saulo Yuda, Roselyne Joseph etc. For More Photos, Click The link -> https://photos.app.goo.gl/h3rGcb4c 91UzQaav6

Earlier a authenticated letter of AUGP USA under the Signature of His Eminence Prof. Dr. Madhu Krishan the Chairman Cum Chief Rector /Chancellor of AUGP USA & Dr. Kiwi Kalloo the Governor from New Jersey, USA; was submitted to Hon'be President of Republic of Tanzania for a Donation of more than 2 Billions US Dollor for the specific purpose of humanitarian, educational projects in Tanzania for over all Socio-Economical & sustainable development of Tanzana was submitted to Hon'ble President of Tanzania by Bishop Eliah Edward Mauza Director cum Peace Ambassador of AUGP USA & his team of more than 80 representatives.

Dr. Eliah Edward Mauza Director cum Peace Ambassador Of AUGP USA, DODOMA, Tanzania.

-ITN

#### **SUBSCRIPTION FORM** TIMES OF PEDIA

issue	Sunscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
	5,000/-	Life

Address:.... ..... Email:.... Contact Phone No..... for donation /life // /10 yrs // /5 yrs subscription The sum of Rupees......(Rs...../-) through cheque/DD No......dt.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address:

Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025

or email: timesofpedia@gmail.com

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi Punjab National Bank, Nanak Pura Branch, New Delhi-110021

A/C No.1537002100017151, IFS Code: PUNB 0153



Ending Someone's thirst is Biggest

Deed of Humanity

#### **ADVERTISEMENT TARIFF** TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

#### **MECHANICAL DATA:**

Language: English, Hindi and Urdu

Printing: Front and Back - 4 Colours, Inside pages - B&W

No. of Pages: 12 pages (more in future)

Price: Rs. 3/-Print order: 25,000 Periodicity: Weekly

Material details: Positives/Format of your advertisements should

reach us 10 days before printing.

Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page

Please Add Rs. 10 for outstation cheques.

50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

#### Bank transactions details of TIMES OF PEDIA

Send your subscriptions/memberships/donations etc. (Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi Punjab National Bank, Nanak Pura Branch , New Delhi-110021 A/C No.1537002100017151, IFS Code: PUNB 0153700

#### P. C Sarkar's Lucknow-Ode to a City" launched in Lucknow by Shahanshah Mirza

The city of Lucknow witnessed the book release Ode to a City, by its son Dr. P C Sarkar. Dr Sarkar a senior scientist by profession, based in Kolkata. Addressing the elite audience at Kaifi Azmi

Auditorium, where his book was released amongst other by the descendants of King Wajid Ali Shah, Shahanshah Mirza, Dr Sarkar said that people are not aware as to why many roads are named after Britishers. They are not aware as to where Latouche is buried or who is Takait Rai, historical value of Balle Gate. Dr Sarkar said it is not a history book but a tribute to Lucknow .as the



title itself suggests. its architectural marvels, and lost monuments, which

unfortunately today are in a very bad shape. Vipul Varshney, a leading

architect of the city and Convener of INTACH aptly mentioned in her address the various activities of INTACH. She said that INTACH in recent past have held various activities highlighting the importance of preserving our heritage and conservation of the monuments.

Mehru jaffer, famous author moderated the discussion, which followed the book release. Denzil Godin was also present on the dias, to grace the occasion.

The function was organized under the aegis of The Lucknow Expression Society, at Kaifi Azmi Auditorium. -ITN

## GAIL (India) Limited : Shri Milind Soman culminates 1,000 km long 'Green Ride' on bicycle from Mumbai to Delhi to raise awareness against air pollution

New Delhi, December 14, 2021: After a 1,000 km long bicycle journey from Mumbai to raise awareness against air pollution, fitness icon Shri Milind Soman reached Delhi where he culminated the 'Green Ride - Ek Pahal Swachh Hawa Ki Ore' powered by GAIL (India) Limited. GAIL Chairman and Managing Director Shri Manoj Jain, Director (Marketing) Shri E S Ranganathan, Director (Finance) Shri R K Jain, Chief Vigilance Officer Smt Shubha Naresh Bhambhani and other senior officials were present on the occasion.

The Green Ride entourage started on December 3, 2021 from Mumbai and passed through Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Haryana before arriving at New Delhi.

Speaking on the occasion, GAIL CMD Shri Manoj Jain said GAIL was always at the forefront of the fight against air pollution. The company's



which strives to raise awareness against the menace has reached netizens over 100 million times. "As part of its commitment towards raising awareness for sustainable and environment friendly lifestyle, GAIL partnered with 'Green Ride – Ek Pehal Swachh Hawa ki Ore' which is an unique initiative by fitness icon Shri Milind Soman to

raise awareness and encourage the people of India to do their bit towards cleaner air," Shri Jain said.

"Delighted, Grateful & Exhilarated! This sums up my journey on cycle from Mumbai to Delhi. The GREEN RIDE was an effort to explore and promote healthier modes of transportation," Shri Soman said. "I hope I was able to create some more awareness

about how we are polluting the air we breathe, and efforts we all can make to reduce this pollution! Every small step that we take, like opting for a car pool, planting a tree, choosing to cycle rather than take a car, quitting smoking and so many other small ways, plays a huge role in making our environment healthier for us and all life on the planet. Will continue to champion for this cause and other important ones through more such initiatives in the future," he added.

Presented by Bank of Baroda and powered by GAIL (India) Limited, Shri Milind Soman interacted with media at various points, met environmentalists, rural students and planted saplings on his route to spread awareness on the issue of clean air. He also interacted with GAIL employees at various places and discussed issues of health, fitness and environment with them.

-Report : Sunit Narula

## Union Minister Sh. Narendra Singh Tomar hails agriculture performance of Uttar Pradesh and congratulates the CM.

Addressing digitally the concluding function of the Uttar Pradesh AgroVision 2021 at Lucknow, the Union Minister, Sh. Narendra Singh Tomar hailed the agricultural performance of Uttar Pradesh, which has broken all previous records in production and procurement. He congratulated the Chief Minister, Yogi for his dedicated leadership in improving upon the condition of farmers through a series of policy measures. Sh. Tomar outlined the priorities of the Government from giving boost to FPOs formation and establishing processing and market linkages. He called upon the industry and investors to work for setting up food processing units in the State. He said when UP grows then whole country grows, as the UP is not only the largest state, but contributes to 15% of the countries farm

production. He said over 2.50 crore farmers of Uttar Pradesh have benefitted by the Kisan Samman Nidhi, which is over 20% of the entire country.

Lamenting on the situation for the withdrawal of the three farm laws, Sh. Tomar congratulated the prime minister for showing sensitivity, as a section of the farmers could not see the benefits that these laws would have offered to farmers by opening up markets, and by increased investments in processing and agri infrastructure. He however said that the Government would make efforts to ensure that the progress of agriculture does not suffer and farmers are able to get better price and more choices to sell their products, despite the repeal of laws. Highlighting the importance of platforms like AgroVision in bringing all key stakeholders in food and

agriculture on one platform and fostering investment and partnerships on one hand and creating awareness among farmers of the latest technologies, Sh. Tomar praised the initiative of Indian Chamber of Food and Agriculture in hosting three day event AgroVision 16-18 December at Lucknow, which was participated by over 100 companies and intitutions from across the country and 20,000 farmers from all over the state.

Earlier inaugurating the event, agriculture minister of Uttar Pradesh, Sh. Surya Pratap Shahi highlighted the performance of the state agriculture in terms of 35% rise in acreage under oilseeds and procurement of over 56 lac MT of food grains. Sh. Shahi called upon the progressive farmers to form more FPOs as institutional system to serve farmers through beter market

linkages and farm services. Speaking on the occasion, additional chief secretary of agriculture, Sh. Devesh Chaturvedi and earlier agriculture production commissioner, Sh. Alok Sinha invited the agri startups, agro exporters and companies to come forward and tap the opportunities in agro sector in the State. The 200% growth in agro exports, especially from Varanasi and Lucknow terminals are setting landmarks in linking farmers to the national and global markets. A number of experts and top government officials and industry CEOs, including Agriculture Commissioner of India, Dr. SK Malhotra and South Asia MD of Bayer CropScience, Mr. D Narain joined the Development Meet on Uttar Pradesh, as part of the AgroVision 2021.

#### What should be the role of India's Chief of Defence Staff? Maroof Raza



Few people, outside those informed about India's higher defence organization, know that the defence of India - as per the Government of India's (Transaction of Business ) Rules of 1961 – is the responsibility of civilians; the defence minister (a political appointee) and the defence secretary (a bureaucrat), and not the service chiefs! The chiefs of India's armed forces are responsible through the defence ministry for the command, training, administration and preparation for a war of their respective services. No wonder, it has led many commentators to say that India has the most absurd civil-military equation for a country with such an impressive military tradition and with all the military challenges it continues to face. These rules, it appears were formulated by copying the British system, which has influenced the structures of India's ministry of defence (MoD) and that of its armed force. However, in the British system, the Defence Secretary is a politician, and a minister their PM's cabinet, whereas, in India, the defence secretary is a civil servant. Even in the American system, the Secretary of State for Defence is appointed by the President, who may neither be a politician nor a bureaucrat, but has cabinet rank. But in India a secretary is a high ranking bureaucrat and not a politician.

Therefore India's armed forces have been insisting on having a military officer as the Chief of Defence Staff (CDS) since the armed forces have a number of professional requirements that need domain expertise, which a generalist bureaucrat doesn't have. However, as a legacy of the Pandit Nehru and Krishna Menon era, the bureaucracy is all over the Indian Ministry of Defence, and all-powerful, but military men say. that they are often neither held accountable - as the defence secretary after the 1962 military debacle, was only posted out to another ministry, while the defence minister and many senior generals resigned and nor is he sufficiently sympathetic to the needs of serving and retired personnel of India's armed forces. Thus, the announcement that India would now have a CDS, has brought some relief in military circles, though there is much to be done before a CDS adequately address our security concerns. In fact, the idea of a CDS, was apparently, first brought up after the 1971 war, when it was suggested that Field Marshal Sam Manekshaw should be made the first CDS. Not only did Manekshaw, soon fall out of favour with Mrs. Gandhi, but his candidature was apparently vetoed also by then Air Chief, ACM PC Lal (with whom Manekshaw, was not quite on talking terms at least during the 1971 war) and

the then Defence Secretary, KB Lal, as Manekshaw was known to bulldoze his way past the bureaucracy.

The matter thereafter lay in limbo for another four decades, as the bureaucracy was quite happy to see that the three service chiefs were not on the same page at least on this issue. Interestingly, the strongest opposition to the idea of the CDS, still comes from the IAF and the IAS lobbies. Even during the Kargil conflict, it is said that the then Army Chief, General Malik, and then Air Chief, ACM Tipnis, had major differences about the use of airpower and helicopter gunships against Pakistani bunkers. Such differences and delays cost lives of soldiers on ground. However, it was eventually resolved and the IAF became a force

multiplier. But, following the Kargil conflict, the Kargil Review Committee (KRC) report, had recommended that a CDS was essential for the demands of modern warfare - which require inter-service cooperation, to achieve our political goals with the limited resources of our armed forces. And thereafter, following the KRC's recommendations, a Group of Ministers supported the idea of CDS and so did the Naresh Chandra committee on defence reforms. As did a study by a team headed by Lt.Gen Shekatkar in 2016, since India's armed forces, have traditionally operated in independent silos, with each service having its own doctrine, its own of equipment purchases, and their own professional traditions and culture.

This has always led to heartburn and wrangling over who would get how much of limited budgets left over for the purchase of equipment for critical military equipment to fight wars. It has to be done with what is left over after the basic needs of the services, like salaries and infrastructure upgrades, are met, with the increasingly dwindling defence budgets. The CDS, once fully operational, could help the government of the day in meeting the requirements of the armed forces, more so, as is known that the advise given by the defense secretary to the Cabinet on our state of military preparedness has been sometimes questionable. For instance, during the Kargil Conflict, the then defense secretary had told the Cabinet that while General Malik was publically stating the army was short of basic weapons to fight Pakistani intruders, there were enough rifles that were available in our ordinance depots. A quick check by army headquarters revealed that there were rifles, but these were of World War II vintage, and it would be suicidal to send our troops in battle with vintage .303's. And even now, with a few

exceptions, a generalist bureaucrat without domain expertise, but responsible for the defence of India, would often be hard put to differentiate between an armoured car and armoured vehicles.

The question now is what should be the role of the CDS? We've had a Headquarters of Integrated Defence Staff (IDS) in the MoD for fifteen years now, which has been in waiting for a CDS, to help it fulfil its roles! To begin, it must be ensured that the CDS, must be a military man from any of the three services but picked for his suitability for the job, ideally after him having been a service chief, and not purely on the basis of seniority, as has been the case until now with the Chairman of

the Chiefs of Staff, which is held by the senior-most service chief. And as the CDS should be the single point of military advice for the Prime Minister and his cabinet, his role must not threaten the civilian bureaucracy in the Ministry of Defence nor the service chiefs and their fiefdoms. Instead, the CDS could be given a proactive role in streamlining our defense and military acquisition processes and facilitating the inter-service sharing of equipment and resources. Equally, the CDS could advise the government on how India's armed forces must prepare for the future challenges of threats in the cyber and space domain as also the better sharing of intelligence inputs. And of course, there is a need to synergize the warfighting doctrines of our three services which are currently tailored to meet their own specific requirements, instead of an 'air-land' or 'air-sea' operation as well as out-ofarea operations beyond India's borders. For this,

he the CDS must be senior to the service chief's, and if we go in for theatre comnands, he must he their overall coordinator.

However, the establishment of theatre commands, which I'm told is also opposed by the IAF, will take time. While our armed forces have been greatly influenced by the British tradition, and though they often quote the American model now – with theatre commands the world over- perhaps, the Chinese model is a better option for India to adopt. In 2016, President Xi Jingping appointed China's first chief of joint staff and divided China's armed forces into theatre commands for managing its military operational needs. Thus, China's Western Command in Chengdu is now focused on India and parts of Central Asia with adequate land and air resources to fight a war in the high Himalayas. India, on the other hand, has a fragmented approach to dealing with the Chinese, with multiple commands of the army (in J&K, Lucknow, and Calcutta), the airforce (in Shillong, and in J&K), and the navy (in Vishakapatnam), all prepared to battle the Chinese threat. In fact, in all, India has 17 military commands and each of them have operational roles that overlap over that of a sister service and a massive logistics tail.

Thus, what India therefore needs are theatre commands that cover all our threats and use our limited resources to the optimum. This writer had proposed the idea of theatre commands about 25 years ago and these could be as follows. A theatre command each to address the threat from China that would start from India's north-east on the Indo-Myanmar border and go along Sino Indian boundary to LAC in Aksai Chin. The other would focus on Pakistan, starting from Siachen Glacier, and go along the LOC and Indo-Pak Border right up to the Rann of Kutch. Both these should be headed always by army officers with adequate components of air-force in particular and some elements of the Navy since their primary threats would be on land. And then a peninsular command, which would run

, which would run from the coasts of Gujarat, right along the Indian coastline, until Bengal and Bangladesh to be headed by a naval officer since their primary role would be to guard against maritime threats and manage out of area operations.

This theatre would have the necessary army and air resources to meet all the contingencies of this theatre. And finally, an air and missile forces command that could be used in addition to the above-outlined commands, to provide air and missile firepower as force multipliers, to any operations India's armed forces might have to undertake, along our land or sea borders. The CDS should be the link between the CCS and the defence minister, to coordinate their operational engagements, without interfering in their roles.

And then there is the issue of nuclear weapons. Though the decision to use them will continue to rest with the PM and his CCS through the defense minister, the CDS could manage their deployment along with the service chiefs, theatre commanders, along with our scientific community. Here, the CDS could play a very important role in coordinating between the civilian leadership and the military headquarters, and he would need to do it, in double-quick time. For this reason itself, the CDS must be given the necessary authority to ensure that we are not fumbling when faced with threats from an increasingly aggressive Pakistan or China. To that extent, India could closely look at America's Goldwater-Nicholas Act that gives their Chairman of Joint Chiefs of Staff (which came into being in 1986) direct access to US President, their supreme military commander, (which in our case would have to be modified for the CDS to

to have direct access to the Defense Minister) but without him interfering with the operational roles of American theatre commanders all over the world. But unlike the US, the CDS in India would need to coordinate with the Indian theatre commanders and the service headquarters since there could be conflicts of professional opinions between the service chiefs and our theatre commanders.

In all this, the bureaucracy in the MoD should retain its own relevance while the CDS with his own headquarters would work to fill the gap of professional knowledge that the bureaucracy suffers from since they are not career military officers but civil servants, who at least in the decisionmaking levels (joint-secretary upwards), shift from the one ministry to another, and are thus familiar with the Government of India's rules and regulations. One major shortcoming of our absurd system, as vet, has been the confusion over the need for critical military equipment. This the armed forces are best placed to handle. To that the extent there is a requirement of having military officers positioned alongside bureaucrats in the MoD. And finally the fear, that has been promoted sometimes by the bureaucracy and intelligence agencies, that a "super-general" (CDS) once appointed could energize the armed forces into taking over the country is ridiculous, to say the least. Nothing can be further from the truth and is an insult to the integrity of India's armed forces, which have remained steadfastly loyal to the Constitution, and the elected government of this country. In fact, their professionalism and their apolitical conduct have been an example to others in the developing

Maroof Raza is Defense analyst, Author and Consulting Editor with Times Now,

## नीट के अलावा भी हैं मेडिकल कोर्सेस में अच्छा भविष्य

एमबीबीएस और बीडीएस भारत में 12वीं के बाद सबसे आम मेडिकल कोर्स हैं, मगर मेडिकल कोर्स के कई मेडिकल और पैरायूनिवर्सिटी हैं, जिनमें प्रवेश के लिए एनईईटी की आवश्यकता नहीं होती है । एनईईटी के बिना ये मेडिकल कोर्स उन छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ट हैं जो एनईईटी के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सके या एमबीबीएसध्बीडीएस नहीं करना चाहते। छम्म्ज के बिना कुछ बेहतरीन मेडिकल कोर्स में बीएसंसी नर्सिंग, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बीएससी साइकोलॉजी, बीएससी बायोमेडिकल साइंस और कई अन्य शामिल हैं। इसलिए, यदि एमबीबीएस के अलावा अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों की तलाश कर रहे हैं, तो इस ब्लॉग में। हम नीट के बिना 12वीं के बाद सबसे अच्छे मेडिकल कोर्स और साथ ही नीट के बिना डॉक्टर बनने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञताओं की सूची देंगे।

नीट के बिना 12वीं साईंस बायोलॉजी के बाद के कोर्स

निर्माः एमबीबीएस और दंत चिकित्सा विज्ञान के बाद निर्मांग एक लोकप्रिय चिकित्सा विशेषज्ञता है और भारत के साथ—साथ विदेशों में कई कॉलेजों में निर्सांग पाठ्यक्रमों के लिए एनईईटी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, आप भारत और विदेशों में एक नर्स के रूप में कई उच्च—भुगतान वाले अवसरों का पता लगा सकते हैं क्योंकि संगठन निर्मंग नौकरियों के लिए भी वीजा प्रायोजन प्रदान करते हैं। भारत में एक पंजीकृत

नर्स का प्रारंभिक वेतन वेतनमान के अनुसार ₹297662 प्रति वर्ष है और इससे भी अधिक हो सकता है।

बीएससी जैव प्रौद्योगिकीः बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस एक 3 साल का अंडरग्रेजुएट कोर्स है जो आणविक और अनुप्रयुक्त जैव रसायन पर केंद्रित है। पाठ्यक्रम विभिन्न शोध परियोजनाओं वाले छात्रों को पर्याप्त ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। नीट के बिना मेडिकल कोर्स करने वाले छात्र बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों का पता लगा सकते हैं।

बीएससी मनोविज्ञानः एनईईटी, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीएससी साइकोलॉजी के बिना सबसे अधिक चुने गए चिकित्सा पाठ्यक्रमों में से एक, सभी क्षेत्रों में कैरियर के अवसरों की एक श्रृंखला के द्वार खोलता है। विकासात्मक और सामाजिक मनोविज्ञान से लेकर अनुसंधान पद्धित तक, बीएससी ६ बीए मनोविज्ञान विषय क्षेत्र से संबंधित विषयों की एक श्रृंखला को कवर करते हैं।

बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजीः एक उभरता हुआ चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र, कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी में बीएससी, कंप्यूटर हार्डवेयर टूल्स के साथ कार्डियोवेस्कुलर बीमारियों और देखभाल जै से इको का िर्ड यो गाफी, माइक्रोबायोलॉजी, लिम्फैटिक टिश्यू इत्यादि से संबंधित विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान करता है। ये पेशेवर विभिन्न गतिविधियों में डॉक्टरों की सहायता करते हैं। तो, अगर आप सोच रहे हैं कि कार्डियोवेस्कुलर तकनीक के लिए नीट

की आवश्यकता है या नहीं तो इसका उत्तर है नहीं! आपके पीसीबी अंक कॉलेजों में प्रवेश पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में स्नातकः बायोमेडिकल इंजीनियरिंग , जिसमें मेडिसिन और इंजीनियरिंग के तत्व शामिल हैं, जीव विज्ञान और चिकित्सा में इंजीनियरिंग की तकनीकों को शामिल करके मानव स्वास्थ्य में सुधार के नए तरीके बनाने पर काम करता है। इस कोर्स को पूरा करने पर, जो 4 साल की अवधि तक चलता है, आपउद्योगों मेंपर्याप्त बायोमेडिकल इंजीनियरिंग नौकरियां पा सकते हैं।

बी फार्माः जो लोग फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बी फार्मा करना एक उपयुक्त विकल्प है। 4 साल की अवधि के साथ, बैचलर ऑफ फार्मेसी ड्रग डेवलपमेंट, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल प्रैक्टिस इत्यादि जैसे क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है। यदि आप इस क्षेत्र में एनईईटी के बिना मेडिकल कोर्स की तलाश में हैं तो फार्मेसी में डिप्लोमा भी तलाशने लायक है।

बीएनवायएसः केवल भारत तक ही सीमित नहीं, योग विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम भी अब दुनिया भर के कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम शरीर को शुद्ध करने और विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए एक्यूपंक्चर, पोषण, हबल दवाओं आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, बीएनवाईएस जैसे एनईईटी के बिना

चिकित्सा पाठ्यक्रम कई लोगों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। आपने अपना 10़2 बीपीसी विषयों के साथ न्यूनतम 45—50: के साथ पास किया होगा।

बीएससी खाद्य प्रौद्योगिकी: खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान रनातक 4 वर्षीय रनातक कार्यक्रम है जो खाद्य खाद्य और कच्चे माल के प्रसंस्करण, विकास, निर्माण और भंडारण पर केंद्रित है। खाद्य प्रौद्योगिकी में डिग्री वाले पेशेवर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अपार अवसर तलाश सकते हैं। बीएससी के अलावा, आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जैसे एनईईटी के बिना अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों का भी पता लगा सकते हैं।

कृषि विज्ञान में बीएससी: कृषि विज्ञान एक बहुआयामी क्षेत्र है जिसमें विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक विषय शामिल हैं। जब कृषि पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने की बात आती है तो बीएससी कृषि विज्ञान छात्रों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प है। 4 साल की अविध के लिए चलने वाला यह कार्यक्रम कृषि प्रबंधन, कृषि मशीनरी, बागवानी और कृषि व्यवसाय से संबंधित अनुसंधान के बारे में ज्ञान प्रदान करता है।

बीएससी जीव विज्ञानः बीएससी बायोलॉजी सबसे अधिक मांग वाला बैचलर ऑफ साइंस कोर्स है जो 3–4 साल की अवधि तक चलता है। जैव विविधता और चिकित्सा निदान से लेकर सिस्टम फिजियोलॉजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य तक, पाठ्यक्रम सिद्धांत कक्षाओं और व्यावहारिक प्रयोगशालाओं दोनों के माध्यम से क्षेत्र का व्यापक ज्ञान प्रदान करता है।

## एक साल या उससे कम में आढ हेल्थकेयर सर्टिफिकेट

यदि आप एक संबद्ध स्वास्थ्य करियर में शामिल होना चाहते हैं, तो आप इसे तेजी से चुन सकते हैं— या सुपर फास्ट! प्रमाणन आवश्यकताओं के प्रकार के आधार पर और जहां आप स्कूल जाने का निर्णय लेते हैं, कुछ कार्यक्रम 12 महीने या उससे कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगले साल इस समय तक आपका पूरा जीवन बदल सकता है।

जब आप जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य सेवा प्रमाणन के लिए त्विरत मार्ग आदर्श होते हैं। यदि आप पहले से ही स्वास्थ्य सेवा में काम करते हैं, लेकिन करियर के रास्ते बदलने की सोच रहे हैं, तो एक छोटा प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको वहां पहुंचाने में मदद कर सकता है।

हमने त्वरित प्रमाणपत्रों की एक सूची तैयार की है जो अच्छी तरह से भुगतान करने वाले 6—महीने के प्रमाणपत्र कार्यक्रमों सहित महान प्रवेश—स्तर की नौकरियों तक तेजी से पहुंच की अनुमति देती है!

फेलोबोटॉमी तकनीशियनः कुछ लोग खून की दृष्टि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबिक अन्य हमारी नसों में बहने वाले लाल तरल के बारे में पर्याप्त पागल रक्त—संबंधी तथ्य नहीं सीख सकते हैं। फेलोबोटॉमी तकनीशियन रोगियों से रक्त लेते हैं और इसे प्रसंस्करण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजते हैं।

फेलोबोटॉमी प्रमाणन कुछ ही हफ्तों में प्राप्त किया जा सकता है। एक बार रोगी का रक्त लेने के बाद, यह फ्लेबोटोमिस्ट की जिम्मेदारी है कि वह इसे प्रयोगशाला परीक्षण के लिए तैयार करे। एक चीसमइवजवउल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ज्यादातर व्यावहारिक है, और प्रमाणित पेशेवर अक्सर इस नौकरी का उपयोग अन्य करियर के लिए एक कदम पत्थर के रूप में करते हैं। प्रमाणनः लगभग 2—6 महीने.

**फार्मेसी तकनीशियन** : हर बार जब आप अपने स्थानीय दवा की दुकान पर जाते हैं, तो संभव है कि आपका सामना फार्मेसी तकनीक से हो। ये संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर एक लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट की देखरेख में नुस्खे भरने, इन्वेंट्री करने और रोगियों और उनकी बीमा कंपनियों के साथ काम करने के लिए काम करते हैं।

एक प्रमाणित फार्मेसी तकनीशियन बनने के लिए, प्रशिक्षण में लगभग तीन महीने लगते हैं, लेकिन इस समय में बहुत कुछ कवर करना होता है। छात्र उचित दवा वर्गीकरण और प्रशासन के साथ—साथ फार्मास्युटिकल शब्दावली और प्रबंधन के बारे में जानेंगे। प्रमाणनः लगभग 9 महीने.

प्रमाणित कार्डिएक मॉनिटर तकनीशियनः यदि आप अधिक परिभाषित भूमिका चाहते हैं, तो कार्डिएक मॉनिटर तकनीशियन के रूप में कार्डियोलॉजी में एक अत्यंत त्वरित मार्ग है। चिकित्सकों और हृदय रोग विशेषज्ञों के निर्देशन में काम करते हुए, ये तकनीक जन्म दोष और बीमारी जैसी हृदय की समस्याओं की जांच के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईकंजी) मशीनों का उपयोग करती हैं।

अपने त्वरित प्रमाणन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान, ईकेजी, तनाव परीक्षण, चल निगरानी, और इन परिणामों की व्याख्या करने के तरीके का अध्ययन करने के लिए कार्डियक मॉनिटर तकनीक की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम की छोटी अवधि के अलावा, कई तकनीकी स्कूल लचीले शेड्यूलिंग की पेशकश करते हैं जो कई छात्रों को पढ़ाई के दौरान काम करने औरध्या अपने परिवार की देखभाल करने का अवसर देता है। प्रमाणनः लगभग 3—6 महीने.

चिकित्सा बिलिंग और कोडिंग विशेषज्ञः बिलिंग और बीमा में गलतियों के कारण अस्पतालों, रोगियों और बीमा कंपनियों को भारी रकम खर्च करनी पड़ सकती है, खासकर अगर किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप जुर्माना या गलत निदान होता है। गलत (और महंग) शुल्कों से बचने के लिए, मेडिकल बिलर्स और कोडर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रियाओं को संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट उद्योग

कोड का उपयोग करके स्वास्थ्य संबंधी बिल और बीमा ठीक से संसाधित किए जाते हैं।

बिलिंग और कोडिंग में एक प्रमाणित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, लेकिन नौकरी के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। प्रमाणनः लगभग 4—9 महीने.

सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्टः सर्जिकल टीम एक लोकप्रिय और एड्रेनालाईन चार्ज अस्पताल के ऑपरेटिंग कमरे, आपातकालीन कमरे, और यहां तक कि चलने वाले देखभाल केंद्रों में करियर पथ है। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट टीम के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं जो अपना समय रोगी और मेडिकल टीम (विशेषकर नर्स, एनेस्थिसियोलॉजिस्ट और सर्जन) दोनों का समर्थन करने वाले ऑपरेटिंग रूम में बिताते हैं।

एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिर्फ एक वर्ष से अधिक के साथ प्रमाणित सर्जिकल तकनीक बनना संभव है । यहां, छात्र सर्जिकल उपकरणों को तैयार करने से लेकर प्रक्रियाओं के लिए तैयार एक सैनिटरी वातावरण सुनिश्चित करने और ऑपरेशन से पहले और बाद में रोगी देखभाल दोनों से सब कुछ सीखने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रमाणनः लगभग 14—17 महीने.

चिकित्सा सहायकः कार्यस्थल की विविधता प्रदान करने वाली नौकरी की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, चिकित्सा सहायक (एमए) प्रमाणन जाने का रास्ता हो सकता है। प्रमाणित एमए आमतौर पर व्यस्त अस्पताल से लेकर छोटे पोडियाट्रिस्ट के कार्यालय तक कई अलग—अलग सेटिंग्स में काम करने में सक्षम होते हैं।

एमए नैदानिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए प्रशिक्षण में प्रयोगशाला तकनीकों और नैदानिक प्रक्रियाओं के साथ—साथ कार्यालय प्रथाओं, रोगी गोपनीयता और रिकॉर्ड कीपिंग शामिल



है | **प्रमाणनः** लगभग 9—12 महीने.

न्यूरोडायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिस्ट (एनडीटी): यदि आप शरीर के भीतर सामान्य और असामान्य विद्युत गतिविधि का अध्ययन करने के विचार से चिंतित हैं, तो न्यूरोफिजियोलॉजी में एक स्वास्थ्य सेवा आपकी गली तक सही हो सकती है।

अपने एनडीटी प्रशिक्षण के दौरान, छात्र मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में विद्युत गतिविधि के बारे में सीखते हैं। फिर उन्हें अभिनय चिकित्सक के साथ रिकॉर्ड करने और परिणामों पर जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ईईजी (इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी) के अलावा, भविष्य के एनडीटी तंत्रिका स्थिति अध्ययन औरध्या पॉलीसोम्नोग्राफी (अन्यथा नींद अध्ययन के रूप में जाना जाता है) का अभ्यास कर सकते हैं। प्रमाणनः लगभग 12—18 महीने.

दंत चिकित्सा सहायकः चिकित्सकीय सहायक एक योग्य दंत चिकित्सक की देखरेख में प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए काम करते हैं जैसे कि नियुक्तियों को निर्धारित करना और बिलिंग का प्रबंधन करना। जब भी दंत चिकित्सक कोई प्रक्रिया करते हैं, दंत सहायक उपकरण पास करने, दांतों को निकालने में उनकी सहायता करने, या एक्स—रे लेने के लिए उपलब्ध होते हैं।

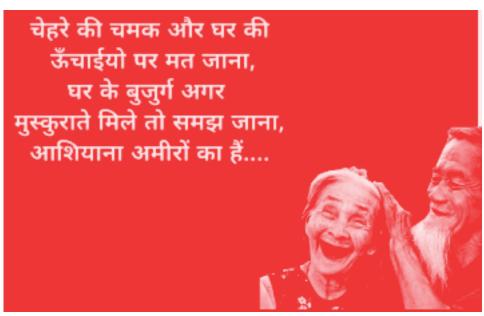
केवल एक वर्ष में, आप राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दंत प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणनः लगभग १ वर्ष.

–एजेंसी

سلسلہ جاری
محمد زبیر شیخ نے ۱۰۰
کتاب پیاری زبان اردو
اقبال لائبریری گوتم
پوری دہلی کو تحفہ
پیش کیااظہار تشکر
مخلص حکیم اجملی
آپ کا نمبر کب
9350578519

السلام علیکم جناب آپ کو
یہ جان کر خوشی ہوگی کہ
علامہ اقبال میموریل
لائبریری میں کتابوں کا آنے
کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ
سے درخواست ہے کہ آپ
بھی تعاون کرے میوات سے
ڈاکٹر قمرالدین ذاکر صاحب
اور مسلم فنڈ نجیب آباد کے
اور مسلم فنڈ نجیب آباد کے
مینیجر جناب اظفارالحق
ذکی صاحب کا شکریہ
ذکی صاحب کا شکریہ











#### Congratulations

TO THE YOUNG AND TALENTED
STUDENTS OF
TALENT ZONE ACADEMY
FOR ACHIEVING SUCH MARKS IN
NEET & IIT.

You all have proved that great things can be achieved through hard works and efforts (would also like to congratulate the faculty team of the Talent Zone Academy for their efforts and giving proper guidance to the students This result marks the first stroke of the beginning

### Sana homoeopathy Aligarh

### HOMEOPATHY MEDICINE

FOR

## DIABETES

9760291236

# हरी सिब्नियां खाएं, तनाव को दूर भगाएं



तनाव आपकी हेल्थ पर तो असर डालता ही है साथ ही आपकी हड्डियों को भी कमजोर कर देता है। हरी सब्जियां खाने से आप रह सकते है तनाव से दूर। दरअसल विशेषज्ञों ने एक शोध कर ये दावा किया है हरी सब्जियों के लगातार सेवन से 62 प्रतिशत तक तनाव को दूर किया जा

विशेषज्ञों का मानना है कि प्याज से लेकर सेब, साग-सब्जियों और फलों में कुदरती तौर पर फाइटोन्यूट्रिएंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। जो एमओ को रोक सकते हैं। लौंग, अजवायन की पत्ती, दालचीनी और जायफल जैसे मसालों में भी ऐसे तत्व होते हैं जो आपके तनाव को दूर रखने में काफी मदद करते हैं। साथ ही जो लोग अपने रोजमर्रा की डायट में सब्जियों और फलों को शामिल करते हैं वो ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं।

जानते हैं कुछ सब्जियों के बारे में और उनके फायदों के बारे में:

#### टमाटर के फायदे

एक शोध की मानें तो सब्जी से लेकर सॉस तक, टमाटर को पकाने पर इसका फायदा दिल के रोगों को कम करने में मददगार हो सकता है। शोधकर्ताओं की मानें तो पकने के बाद टमाटर में लाइको पीन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण बढ़ जाते हैं और हर रोज 80 ग्राम टमाटर के सॉस का सेवन हाई फैट डाइट के प्रभावों को कम करता है और धमनियों में रक्त के प्रवाह को ठीक करता है।

#### बंद गोभी के फायदे

बंद गोभी उन गुणकारी सब्जियों में से एक है जो आपके शरीर से फैट कम

करने में कारगर साबित होती है ये वजन कम करने के लिए रामबाण का काम करती है क्योंकि इसमें वसा कम और फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है। ये विटामिन के से भरपूर है जो दिमाग के लिए बहुत लाभदायक है। ये अलजाइमर तक को रोकने में मदद करता है। लाल पत्ता गोभी और भी ज्यादा गुणकारी होती है।

#### त्रई के फायदे

बहुत सारे लोगों को तोरई की सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं हैं लेकिन तोरई खाना हमारे स्वास्थ्य के

लिए बहुत ही फायदेमंद होता हैं। इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता हैं। तोरई का प्रयोग मधुमेह, नेत्र रोग, पीलिया, संक्रमण, त्वचा रोग जैसे कई अन्य बीमारियों के इलाज में किया जाता है।

#### खीरे खाने के फायदे

खीरा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जियों में चौथे नंबर पर आता है और इसे हमारे स्वास्थ के लिए बेहतर माना जाता है। इतना ही नहीं, खीरे को सर्वोत्तम आहार माना गया है। खीरा ना केवल सेहत के लिये ही अच्छां माना जाता है बल्कित यह बालों और त्व।चा को भी सुंदर बनाता है। खीरा कब्ज से मुक्ति दिलता है। साथ ही पेट की गैस, एसिडिटी, छाती की जलन में नियमित रूप से खीरा खाना लाभदायक होता है। जो लोग अपने मोटापे से परेशान रहते हैं, उन्हें सुबह इसे खाना चाहिये। कटे खीरे में नमक, काली मिर्च और नींबू डालकर खाने से ये स्वादिष्ट तो लगता ही है साथ ही खाना पचाने में मदद भी करता है। खीरे के रस में दूध, शहद और नींबू मिलाकर चेहरे और हाथ पैर पर लगाने से त्वचा मुलायम और चमकदार भी हो जाती है।

टाइट लेगिंग को छोड़ें इंफोक्शन से बचें



अगर आप भी लेगिंग पहनने की शौकीन हैं तो संभल जाएं। आपको भले ही ना पता हो लेकिन लेगिंग पहनना आपके लिए खतरनाक हो

सकता है। हाल ही के एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि टाइट लेगिंग पहने से आपको कई तरह के स्किन इंफेक्शन हो सकते हैं।

न्यूयोर्क के सिनायी होस्पीटल के डॉ जोश जेशिचनर ने कहा है कि टाइट लेगिंग या कोई भी टाइट गारमेंट्स पहनने से बॉडी का ऑयल और भी बढ जाता है। जिससे आपके स्किन को ब्रिथींग नहीं मिल पाती। इसके साथ ही यह आपके स्किन मॉइस्चराइजर भी खत्म कर देती है। इसकी वजह से स्किन में स्ट्रेच मार्क्स होने का भी खतरा बढ जाता है। आपको बता दें कि रिसर्च में यह भी

पहनने पर फंगल, दाद- खुजली, लाल चकते, रैसेज और यीस्ट इंफेक्शन जैसी प्रॉबलम का सामना करना पड सकता है। आप लेगिंग की जगह एक्टिव वियर या जिम ट्राउजर पहन सकती हैं। जिम ट्राउजर और एक्टिव वियर लेगिग के मुकाबले ज्यादा हवादार होती है। इससे आपके स्किन में नमी बने रहेगी और इन्फेक्शन का खतरा भी रहेगा।